

ग्रामीण बैंक की भूमिका एवं समस्याओं पर एक विवेचना

डॉ० ओम प्रकाश साहु

व्याख्याता

श्रम एवं समाज कल्याण विभाग,

सीता राम साहु कॉलेज, नवादा. बिहार |

सार

जहाँ आज हम आर्थिक उदारीकरण के परिवेश को अपना रहे हैं। ऐसी स्थिति में कृषि एवं ग्राम उद्योग का विकास अपेक्षाकृत तेजी से नहीं हो रहा है इसका जहाँ एक और ग्रामीणों की ऋण ग्रस्तता है दूसरी और संसाधनों के पर्याप्त होने के बाद भी वित्त के आभाव में उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कृषि अपेक्षाकृत असंगठित व्यवसाय है। इसकी सफलता या असफलता बहुत कुछ मौसम पर निर्भर होती है। इसके अलावा किसानों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों में स्पष्ट रूप से उत्पादक और अनुत्पादक में भेद कर पाना आसान नहीं होता। इसलिये बैंकों ने के लिये या उससे संबंधित दूसरे कार्यों के लिए ऋण देने में प्रायः दिलचस्पी नहीं दिखाई है। और लम्बे असे तक किसान ऋण के लिये मुख्य रूप से सहकार और महाजनों पर निर्भर रहे हैं।

मुख्य शब्द : ग्रामीण, बैंक, किसान, ऋण, इत्यादि।

प्रस्तावना

ग्रामीण बैंकिंग से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त बैंकिंग सुविधाओं से है जिसके अंतर्गत ग्रामीण जनता को अपने बचते जमा करवाने आवश्यकता के समय उन्हें ऋण देने, वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय में सहायता करने धन के हस्तांतरण की सुविधा देने आदि से संबंधित बातें शामिल की जाती है। जो व्यक्ति या संस्थाएं इन कार्यों को करती है उनको ग्रामीण बैंक कहते हैं।

भारत में जो ग्रामीण बैंक की सुविधा वर्तमान में मिल रही है वे शहरी बैंकिंग सुविधाओं की तुलना में बहुत ही कम है अतः उनमें वृद्धि की जानी चाहिए वर्तमान में ग्रामीण बैंक इन का कार्य निबंध संस्थाएं करती है

1. साहूकार या महाजन तथा देसी बैंक
2. सहकारी समितियां एवं
3. व्यापारिक बैंक
4. ग्रामीण बैंक

1. साहूकार या महाजन तथा देसी बैंक : साहूकार या महाजन तथा देसी बैंक महाजन से उस व्यक्ति से है जो अपने ग्राहकों को समय समय पर ऋण देता है तथा देसी बैंकर से और उस व्यक्ति या संस्था से है जो ग्राहकों को ऋण देने के अतिरिक्त जन विकास करती है तथा लेन-देन भी करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार, महाजन देसी बैंक बहुत प्रचलित है ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह अपने अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं क्योंकि यह सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए लोन देते हैं इनकी ऋण देने की पद्धति सरल है तथा औपचारिकताएं कम हैं लोन लेने वालों को ये व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। यह मूलधन वापिस पर अधिक जोर नहीं देते हैं। लेकिन इनमें कुछ दोष पाए जाते हैं जिनके कारण इनकी आलोचना की जाती है यह दोष है यह ब्याज काफी ऊंची दर से लेते हैं। लेते समय पूरे वर्ष की ब्याज काट कर ही देते हैं। साथ ही वापसी पर कोई रसीद नहीं देती हैं। ऋण लेने वालों के कोरे कागज पर





हस्ताक्षर करा कर रख लेते हैं जिन पर बाद में रकम लिखकर बेईमानी करते हैं। फसल को आने से पूर्व ही कम मूल्य पर खरीदने का सौदा कर लेते हैं।

2. **सहकारी समितियां या बैंक:** ग्रामीण बैंक का दूसरा साधन सहकारी समितियां या बैंक है जो एकाएक अधिक व्यवसायिक बैंक से अधिकांश कार्य करती है। जन निपेक्ष स्वीकार करती है ऋण प्रदान करती है कृषि उपज को बेचने में सहायता करती है आजकल इस प्रकार की 94 हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। इन समितियों के द्वारा 1950 से 51 में ₹24 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए हैं जो 1980-81 में बढ़कर 1656 करोड़ रुपए हो गए हैं।

3. **व्यापारिक बैंक:** 30 जून 1982 को देश में विभिन्न व्यापारिक बैंकों के 39177 कार्यालय में शाखाएं कार्यरत थे जिनमें से 203988 अर्थात् 52 प्रतिशत कार्यालय शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। व्यापारिक बैंकों के कार्यालय वे सभी कार्य करते हैं जो एक आधुनिक बैंक का शहरी कार्यालय शाखा करती है। यह व्यापारिक बैंकों में स्टेट बैंक उसकी सहायक बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक सभी अनुसूचित व गैर अनुसूचित शामिल है।

4. **ग्रामीण बैंक:** सितंबर 1975 के एक अध्यादेश के आधार पर इन बैंकों की स्थापना के लिए कार्यवाही की गई। क्षेत्रीय बैंक की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का विकास करने के लिए कृषि व्यापार वाणिज्य उद्योग व अन्य उत्पादन क्रियाओं के लिए दिन व अन्य सुविधाएं प्रदान करता है यह असली राय की विशेषता कृषि खेतिहर श्रमिकों कारीगरों लघु उद्योग कर्ताओं को प्रदान की जाएगी 2 अक्टूबर 1975 को ऐसी पांच बैंक स्थापित किए गए जिनकी संख्या जून 1982 को बढ़कर 121 हो गई है इस बैंक की पूंजी ₹1 करोड़ रखी गई है लेकिन प्रताप जी केवल 25 करोड़ रुपए है जिसका 50% केंद्र सरकार द्वारा 15% संबंधित राज्य सरकार द्वारा विशेष 25% प्रयोजन बैंक द्वारा प्रदान किया गया है। 30 जून 1982 को इन 121 शाखाएं राज्य के 207 जिले में कार्य कर रही हैं

इन बैंकों की मुख्य विशेषताएं यह है कि इनका कार्य क्षेत्र छोटा होता है इन बैंकों की शाखाओं में अधिक कर्मचारी स्थानीय होते हैं इनका कार्य संचालन एवं संगठन कम लागत पर किया जाता है। इन बैंकों का मुख्य कार्य ग्रामीणों व किसान की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की समस्याएं

भारतीय बैंक व्यवस्था यदि 200 वर्ष पुरानी है तथा 100 वर्षों में इनका काफी विकास हुआ है लेकिन फिर भी यह मैं तो सुदृढ़ एवं शक्तिमान बन पाई है और न पाश्चात्य देशों की भांति यह पूर्ण बैंकिंग सुविधाएं दे पाए हैं क्योंकि इसकी कुछ समस्याएं या कमियां हैं जो निम्नलिखित हैं

1. **अनियमित विकास:** भारत में अधिकांश बैंकों ने बड़े-बड़े शहरी क्षेत्रों में ही शाखाएं खोली है जिससे एक और प्रतिस्पर्दा बड़ी है मैं दूसरी और उन स्थानों पर विकास में पूरे जहां उनकी स्थापना होना बैंकिंग विकास एवं दोनों स्थानों के लिए चित्रकार था ग्रामीण क्षेत्रों में तो आधुनिक बैंकिंग पर्दा अभाव सहित रहा है लेकिन 1969 के 14 वर्ष 1980 में छह बैंकों की राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप सरकारी नीतियों में परिवर्तन होने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होने लगी है लेकिन फिर भी वे प्राप्त संख्या में नहीं है देश की 6% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है लेकिन वहां कुल बैंकों की 52 प्रतिशत की शाखाएं हैं भारत में प्रति 18000 की आबादी पर चेक बैंक शाखा है लेकिन विभिन्न राज्यों में स्थित भिन्न है पंजाब में 10 हजार की आबादी पर बैंक शाखा है असम में 35000 की आबादी पर एक जबकि केंद्र शासित प्रदेश के छह हजार की आबादी पर एक।



2. **आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का अभाव:** यदि भारत में बैंकों का काफी विकास हुआ है लेकिन फिर भी यह बैंक आधुनिक बैंकिंग सेवाओं देने में शिक्षक जाते हैं भारत में आज भी व्यक्तिगत ऋण व्यवस्था का अभाव है यदि इस संबंध में पिछले कुछ वर्षों में कुछ बैंकों ने शुरुआत की है लेकिन उनका व्यापार इस संबंध में नहीं है।
3. **जन निपेक्ष कम यात्रा में:** भारतीय बैंकों में प्रति व्यक्ति जमा 232 रुपए है जो बहुत ही कम है जन्म निष्पक्ष कम यात्रा में होने के कारण बैंकों की क्रियाएं भी सीमित मात्रा में हो पाती है जन्म निश्चित के कम होने के कारण इस प्रकार हैं भारतीय जनता को प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है अतः उनकी बचते कम होती हैं होती ही नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों की वस्तु को एकत्रित करने के लिए प्राय उपलब्ध नहीं है भारत में बैंक प्रणाली का प्रयोग सीमित मात्रा में होने के कारण भुगतान नगर होते हैं अतः बैंकों में बकाया कम हो जाते हैं बैंकों के कर्मचारी ग्राहकों के साथ उचित एवं व्यवहार नहीं करते हैं जिससे जाग्रता बैंक में जमा करना पसंद नहीं करता है सरकार द्वारा प्रतिवर्ष ऋण लेने से बैंकों का जमा कम मात्रा में ही मिल पाती है भारत में सामान्य मूल्य वृद्धि एवं अधिकरण कर लगने की परिवर्ती पिछले कई वर्षों से चल रही है इससे बचत करने से शक्ति पर प्रभाव पड़ा है
4. **लघु एवं दुर्बल बैंक:** अनुसूचित बैंक स्टेट बैंक पैसा चेक करता बैंकों को छोड़कर जो बैंक निजी क्षेत्र में रह गए हैं वह छोटे एवं दुर्लभ है उनके पास कुल बैंकिंग प्रणाली की जमा का केवल 6% ही है इससे इन बैंकों को अपनी क्रियाओं से रिश्ता करने में कठिनाई होती है।
5. **अकुशल संगठन:** भारत में अधिकांश बैंकों का संगठन कुशल नहीं है उनके अनेक संचालन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बैंकिंग व्यवसाय के बारे में प्राप्त ज्ञान नहीं है यही नहीं बैंकों में अनेक आर्थिक एवं नैतिक अनियमितताएं होती है भारतीय बैंकों में अधिकारियों की भरमार है अमेरिका में एक अधिकारी जितना कार्य संपन्न करता है उतना कार्य भारत में नंबर अधिकारी करते हैं
6. **यंत्रीकरण का भाव :** भारतीय बैंकों का अधिकांश कार्य मानव द्वारा किया जाता है जिसके फलस्वरूप बैंक में वृद्धि होती है तथा जनता को उचित सेवा नहीं मिल पाती है अमेरिका में चेक किया भुगतान 2 मिनट में हो जाता है जबकि भारत में कम से कम 30 मिनट में इसका कारण यही है कि अमेरिका में यंत्रीकरण है जिसके ऊपर फल स्वरूप सभी कार्य अतिशीघ्र हो जाती हैं
7. **प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव:** भारतीय बैंकों की एक समस्या प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है यहां पर कर्मचारियों को सेवा करने से पूर्व कोई परीक्षण नहीं दिया जाता है और भर्ती के पश्चात ही देगी काम पर लगा दिया जाता है

उपसंहार

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पृष्ठ भूमि में कृषि एवं ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में ग्रामीण बैंकों के योगदान में उदारता अत्यंत आवश्यक है। ताकि ग्रामीण कृषकों को सही ऋण उपलब्ध हो सके जिससे वे कृषि कार्य सम्पन्न कर अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सके। ग्रामीण कृषकों के आर्थिक विकास में वित्त की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। जहाँ तक ग्रामीण कृषकों के विकास का प्रश्न है ग्रामीण बैंक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण कृषकों को अधिकाधिक सुविधायें प्रदान करने कृषि एवं कृषकों के आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने पर अधिक बल दिया जा रहा है। जो कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। " क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केवल ग्रामीण ऋण प्रदान करने वाली संस्थामात्र नहीं हैं। वे इससे कहीं अधिक हैं। वे बैंक प्रेरित ग्रामीण विकास का एक जरिया है।"



सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

- [1] अग्रवाल एन.एल, भारतीय कृषि का अर्थशास्त्र।
- [2] डॉ. एन. माथुर और पी.सी. जैन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली।
- [3] गौड़ श्यामलाल, विकासमान बैंकिंग एवं ग्रामीण विकास।
- [4] जैन पी.सी. भारत के कृषि विकास।
- [5] जाट. बी.सी. ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका, 1990।
- [6] खन्ना, श्री एस.एन. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के व्यवसाय का विकास, 1990।